NOES

Abraham, Shri K. M
Anirudhan, Shri K.
Atam Das, Shri
Banerjee, Shri S. M.
Brij Bhushan Lal, Shri
Chakrapani, Shri C. K.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chauhan, Shri Bharat Singh
Deo, Shri P. K.
Fernandes, Shri George
Ghosh, Shri Ganesh
Gopalan, Shri P.
Gupta, Shri Kanwar Lal
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri Jagannath Rao
Kandappan, Shri S.
Kripalani, Shri J. B.
Kuchelar, Shri G.
Kundu, Shri S.
Limaye, Shri Madhu
Madhok, Shri Bal Raj
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Janeshwar
Modak, Shri B. K.
Mulla, Shri A. N.
Nair, Shri Vasudevan
Nambiar, Shri
Nayanar, Shri E. K.
Patil Shri N. R.
Ramabadran, Shri T. D.
Sheth, Shri T. M.
Sivasankaran, Shri
Sreedharan, Shri A.
Suraj Bhan. Shri
Tyagi, Shri Om Prakash
Viswanatham, Shri Tenneti

MR. DEPUTY-SPEAKER : The result* of the division is :

Ayes : 76 ; Noes : 37.

The motion was adopted.

SHRI TENNETI VISWANATHAM introduce the Bill.

15.20 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Omission of article 314)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAM NIWAS MIRDHA) : As a matter of substance I have no objection to the objects of this Bill nor to its introduction. But there are certain constitutional and procedural matters which I think it is my duty to bring before you and the House. I would refer to Art. 117 (1) which reads as follows :

"A Bill or amendment making pro-

श्री प० ला० **बारूपाल** : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूँ ।

MR. DEPUTY SPEAKER : Shri Mrityunjay Prasad—not here. Shri Tenneti Viswanatham.

JUDGES (INQUIRY) AMENDMENT BILL†

(Amendment of Sections 3, 4 and 6)

SHRI TENNETI VISWANATHAM (Visakhapatnam) : I beg to move that leave be granted to introduce a Bill to amend the Judges (Inquiry) Act, 1968.

MR DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Judges (Inquiry) Act, 1968."

The motion was adopted.

*The following Members also recorded their votes for AYES : Sarvashri T. Ram and Vidya Dhar Vajpai.

†Published in the Gazette of India Extraordinary Part II. Section 2, dated 31-7-70.

[Shri Ram Niwas Mirdha]

vision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of article 110 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President.. "

Now Art. 110 (1) says :

"For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely :— ...

(b) the regulation of the..."

SHRI MADHU LIMAYE : It has been disposed of last time.

यह नये मन्त्री हैं, इसलिए फिर से आपत्ति उठा रहे हैं ।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, इस बिल के प्रति हमारा विरोध नहीं है । लेकिन यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं संवैधानिक स्थिति को सदन के समक्ष रखूं, ताकि इस बिल में कोई कमी न रह जाये । मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार फिर भी इस बिल का समर्थन करेगी और राष्ट्रपति से यह निवेदन करेगी कि वह इसके बारे में अपना रीकमेंडेशन दे दें ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस बारे में बहस हो चुकी है । संविधान के अनुच्छेद 314 को हटाने से आई सी० एस० अफसरों की तनख्वाह और पेन्शन आदि पर कोई असर नहीं पड़ता है । यह विधेयक तो एक एनेबलिंग प्राविजन है । इसके बाद सरकार को सबस्टेंटिव लेजिसलेशन लाना पड़ेगा, जिसमें फ़िनांशल प्राविजनज होंगे । संविधान में जो वादा किया गया है, उसको हटा देने के बाद सरकार इस बारे में सबस्टेंटिव लेजिसलेशन ला सकती है । संविधान में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है । पिछली बार यह मुद्दा उठाया गया था और यह रूलिंग दिया जा चुका है कि राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है । नये-नये कानून मन्त्री बनते हैं और नये-नये सुझाव लाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : वह गृह मन्त्री हैं ।

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, बावन पत्तो का इतना रीशफ़ल हुआ है कि हमको पता नहीं है कि कौन क्या है । मैं समझता था कि यह कानून मंत्री हैं । इस बारे में आपका निर्णय हो चुका है कि संविधान के अनच्छेद 314 को हटाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

MR. DEPUTY SPEAKER : This Bill is identical with the one which was discussed in the House on a previous occasion. That was not passed by the requisite majority. Therefore, I think the Bill is quite in order.

Now the question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

श्री मधु लिमये : मैं विधेयक को पेश करता हूँ ।

UTTAR PRADESH LEGISLATIVE COUNCIL (ABOLITION) BILL*

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई-दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद् के उत्सादन तथा तत्सम्बन्धी अनुपूरक, प्रासंगिक और अनुवर्ती विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 31-7-70.